प्रेषक,

डी**०एस० गर्ब्याल,** सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

0279295

शहरी विकास अनुमाग-2

देहरादून : दिनांक अस्ट्रूबर, 20

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 में नगर पंचायत, पोखरी (चमोली) को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पंचायत, पोखरी के पत्रांक—17 / 2—2 / अनुदान / 2016—17, दिनांक 08.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, पोखरी के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार कुल ₹ 15.23 लाख (रूपये पन्द्रह लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:— (धनशांश क्ल लाख में)

 क्र.सं.
 कार्य का विवरण
 स्वीकृत धनशशि

 1.
 बार्ड नं0—1 में डामर से ब्लॉक कार्यालय तक मार्ग निर्माण।
 3.85

 2.
 वार्ड नं0—4 में हाप्रला मोटर मार्ग से बनसारी तोक तक मार्ग निर्माण।
 3.76

 3.
 वार्ड नं0—6 में देवस्थान से बगरधार तोक तक मार्ग निर्माण।
 4.11

 4.
 वार्ड नं0—7 में कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से सिन्थवाल तोक तक मार्ग निर्माण।
 3.51

 योग—
 15.23

- 2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जा रही है:--
- उक्त धनराशि कुल ₹ 15.23 लाख (रूपये पन्द्रह लाख तेईस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, पोखरी को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी।
- उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- 3. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की puplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी /अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 4. स्वींकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- 5. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुरितका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत किये गयै शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरवायी होगी।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं / कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
- 8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

- 9. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्मत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- 10. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

11. निर्साण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

- 12. निर्माण कार्य लोक निर्माण विमाग द्वारा जारी नवीन एसाओ०आर० के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 13. धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकैदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- 15. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूपों पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 3— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (- '20 सहायक अनुदान / अशदान / राज सहायता के नामे ₹ 11.88 लाख अनुदान सं0—30 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (- '42—अन्य व्यय के नामे ₹ 2.90 लाख तथा अनुदान सं0—31 के लेखाशीर्षक— 2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—सं0—31 के लेखाशीर्षक— 2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191— स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05— मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (-20 सहायक अनुदान / अशदान / राज सहायता के नामे ₹ 0.45 लाख डाला जाएगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/xxvII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी—s.4.6////ह....०/--ऽं के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

8 1611 300016 8.1611 310017

भवदीय, (डी)(प्स० गर्ब्याल) सचिव।

<u>संख्या-1712(1)/IV(2)-शा0वि0-2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आर्डिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- जिलाधिकारी, चमोली।
- वरिष्व कोषाधिकारी, देहरादून।
- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून)
- वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

- 9. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
- 10. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपिरहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

11. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

- 12. निर्मीण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 13. धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

15. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूपों पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता=03—नगरों का समेकित विकास—05—मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "20 सहायक अनुदान / अशदान / राज सहायता' के नामे ₹ 11.88 लाख, अनुदान सं0—30 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "- '42—अन्य व्यय के नामे ₹ 2.90 लाख तथा अनुदान सं0—31 के लेखाशीर्षक— 2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191— स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05— मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "05— मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "05— मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "05— मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "05— मिलन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "05— मिलन बस्ती विकास होता जाएगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/xxvII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी—S...म.५/// के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

8 16113000/6

मवदीय, (डी०एस० गर्ब्याल) सचिव।

संख्या— 1912(1)/IV(2)-शावि0-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- जिलाधिकारी, चमोली।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- वित्त अनुभाग−2 / संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

7. निर्देशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।

बंजंट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

Barrier Barrier Barrier and the control of the cont

and were the first transfer of the conjugate of the first of the conjugate of the conjugate

the single this are the second of the second of the second of

and the straight of the term of a significant and a significant and the significant an

erra Grand de la companya de la com

garan reference established and a second contraction of the second con

a linguage the contract of the

9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पोखरी।

That is the state of the state

land the company of the first section

project in the second of the s

10. गार्ड बुक ।

आज्ञा हो, (<u>))</u> (डी०एम०एस० राणा) उप सचिव।